Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
July-December 2022 3(2), 1433–1437

SAARC: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

सार्क: अवसर एवं चुनौतियाँ

Vinod Kumar [1]

[1] SF, Post Doctorate, Ph.D., M.Phil., UGC NET & Lecturer, Department of Political Science, Government College Bahadurgarh, Haryana, India

Corresponding Author

Vinod Kumar, vinodkchahar@gmail.com

DOI
10.29121/shodhkosh.v3.i2.2022.6364

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2022 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

English: South Asian Association for Regional Cooperation is an organization that promotes regional cooperation and economic integration among South Asian countries. SAARC is an organization that brings together eight countries on one platform. Countries like Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka are its members. In the changing world scenario, the political and economic ambitions of the superpowers have systematically ended the immense possibilities of the rise of the global south. The proof of this is South Asia and the regional organization of these countries, SAARC. The present research paper throws light on its conceptual structure, opportunities, challenges and future prospects of this organization. Apart from this, it also throws light on the shared cultural and customs that present it as a well-organized southern unit despite the distinct national identity of these countries.

Hindi: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन एक ऐसा संगठन है जो दक्षिण एशियाई देशों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। सार्क एक ऐसा संगठन हौ जो आठ देशों को एक मंच पर लाता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे राष्ट्र सदस्य हैं। बदलते हुए विश्व परिदृष्य में महाशक्तियों की राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं ने वैश्विक दक्षिण के उत्थान की अपार संभावनाओं को सुनियोजित तरीके से समाप्त कर दिया है। इसका प्रमाण दक्षिण एशिया तथा इन देशों का क्षेत्रीय संगठन सार्क है। प्रस्तुत शोध पत्र इसकी संकल्पनात्मक संरचना, इस संगठन के अवसरों, चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त उन साझा सांस्कृतिक और रीति-रिवाजों पर भी प्रकाश डालता है जो इन देशों की विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान के बावजूद इसे एक सुसंगठित दक्षिणी इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

Keywords: Saarc, SaarcAsean, Bilateral Trade, Power Struggle, South Asia, Bimstec Sub-Regional Initiative, Regional Organization, Regional Integration, सार्क, आसियान, द्विपक्षीय व्यापार, शक्ति संघर्ष, दक्षिण ऐशिया, बिम्सटेक उप-क्षेत्रीय पहल, क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय एकीकरण

1. प्रस्तावना

1.1. शोध प्रविधि

इस शोध पत्र को पूर्ण करने के लिए मुख्य रूप से द्वितिय स्त्रोतों का सहारा लिया गया है इनमें विभिन्न पत्रिकाओं में छपे लेख तथा अनेक पुस्तकें सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त सार्क सम्मेलनों में पारित घोषणा पत्रों का भी सहारा लिया गया है।

2. परिचय

अन्त्रराष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं की दृष्टि से दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है विश्व के कुल आबादी के लगभग एक-चैथाई लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं। यह क्षेत्र कृषि, खनिज एवं जलीय संसाधनों की अनेक सम्भावनाएँ अपने क्षेत्र में समाए हुए हैं। परन्तु इसके साथ ही यह क्षेत्र अपनी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण एवं आतंकवाद तथा राजनीतिक अस्थिरता के लिए भी प्रसिद्ध है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दक्षिण एशिया के सात देशों के क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 1985 में ढाका में आयोजित

शिखर सम्मेलन में की गई थी। इस संगठन को स्थापित करने के लिए बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जिया-उर-रहमान ने पहल की थी। सार्क की स्थापना के अवसर पर इसके सभी सात सदस्य देशों ने अपने अभिभाषणों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग के लिए इस क्षेत्र के विशाल प्राकृतिक संसाधनों तथा संभावनाओं को रेखांकित किया। तथा इस सम्मेलन के घोषणा पत्र में यह सुनिश्चित किया गया कि सभी राष्ट्र सामूहिक रूप से एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, एकता, संप्रभुता तथा सुरक्षा के माध्यम से विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्रिय सहयोग संघ की उत्पति को एक प्रमुख सीमा चिन्ह, युगान्तकारी घटना तथा दक्षिणी एशिया में क्षेत्रीय शक्ति संरचना के नए युग का प्रारम्भ बताया। अतः सार्क की स्थापना इस क्षेत्र में संघर्ष के स्थान पर सहयोग, अविश्वास के स्थान पर सौहार्द और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से गरीबी उन्मूलन का साक्षा दर्शन रखा गया।

3. सार्क संगठन की कार्यप्रणाली

सार्क का ढांचा मुख्य रूप से सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों, विदेश मंत्रियों और स्थाई समिति जैसे अंगों से मिलकर बना है इसके अतिरिक्त इस संगठन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पारस्पतिक सहयोग के लिए कई प्रकार के निकाय भी स्थापित किए गए हैं जो निम्म प्रकार से हैं:

- शिखर सम्मेलन
- मंत्री परिषद
- स्थाई समिति
- प्रोग्रामिंग समिति
- कार्य समिति
- सचिवालय

3.1. सार्क के सहयोग के क्षेत्र

इस संगठन का प्रयोजन इस क्षेत्र के लोगों का कल्याण करना, सामूदायिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और एकजुटता को विकसित करना तथा अन्तराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ जुड़ना है। सदस्य देशों द्वारा सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र निश्चित किए गए हैं:

- कृषि और ग्रामीण विकास
- निवेश और वाणिज्यिक विवादों का निपटान
- जैव प्रौद्योगिकी
- सांस्कृतिक सहयोग
- आर्थिक और व्यापार
- शिक्षा
- ऊर्जा
- पर्यावरण
- वित्त
- खाद्य सुरक्षा और खाद्य बैंक
- वित्तपोशण तंत्र
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
- गरीबी उन्मूलन
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- सुरक्षा पहलू
- आतंकवाद
- पुलिस मामले

- पर्यटन
- समाजिक विकास

3.2. सार्क क्षेत्रीय केंद्र

सार्क देशों में अनेक क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की गई है ताकि सार्क देशों में व्याप्त समस्याओं का समाधान तथा सहयोग किया जा सके। जो इस प्रकार हैं:

- सार्क कृषि केन्द्र, ढाका
- सार्क मौसस विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, ढाका
- सार्क क्षय रोग और एच आई वह। एड्स केन्द्र, काठमांडू
- सार्क प्रलेखन केन्द्र, मालदीव
- सार्क सूचना केन्द्र, नेपाल
- सार्क मानव संसाधन विकास केन्द्र, ढाका
- सार्क तटीय क्षेत्र प्रबंधन केन्द्र, मालदीव
- सार्क उर्जा केन्द्र, पाकिस्तान
- सार्क आपदा प्रबंधन केन्द्र, भारत
- सार्क सांस्कृतिक केन्द्र, श्रीलंका

3.3. सार्क सिद्धांत

सभी राष्ट्रों की आम सहमति से कुछ मूलभूत सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है, जिनके माध्यम से साझा हितों की पूर्ति की जा सके। इस संगठन के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:

- इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य पूर्व निर्धारित सहयोग के क्षेत्रों में मिलकर काम करके; सदस्य राष्ट्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करना है।
- राष्ट्रों की संप्रभुता, समानता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा अन्य राष्ट्रों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा पारस्परिक लाभ के आदर्शों के प्रति समर्थन, संघ के ढांचे के अन्दर सहयोग का आधार है।
- इस प्रकार का पारस्परिक सहयोग, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प नहीं बल्कि उसका पूरक होगा।
- इस संगठन के मंच से द्विपक्षीय विवाद के राजनीतिक मामलों को नहीं उठाया जाएगा।
- वैश्विक एवं क्षेत्रीय संदर्भो के संदर्भ में निर्णय आम सहमति से लिए जायेंगे।

3.4. सार्क देशों के मध्य समस्याएँ

जैसे जैसे क्षेत्रीय शक्ति संरचना में परिवर्तन होता है इसका प्रभाव उन सभी राष्ट्रों की आंतरिक एवं बाह्य राजनीति पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अतः सार्क देशों के अनेक विवादों एवं समस्याओं का प्रभाव सार्क के सक्रिय संचालन पर पड़ा। इस संदर्भ में मुख्य विवाद एवं समस्याएँ निम्नलिखित हैं:

- भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवाद।
- सदस्य देशों के मध्य विश्वास, आपसी सुरक्षा चिन्ताएँ और शत्रुता।
- भारतीय प्रभुत्व से सदस्य देशों में भय।
- सार्क देशों की अस्थिर एवं कमजोर वित्तीय स्थिति।
- सार्क के चार्टर में स्वयं कुछ विसंगतियाँ है, क्योंकि इसमें विवादास्पद और द्विपक्षीय विवादों पर चर्चा न करने का प्रावधान है।

- दक्षिण एशिया एक मजबूत लोकतांत्रिक क्षेत्र नहीं रहा है।
- लोगों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क का अभाव।
- दक्षिण एशिआई देशों में मजबूत बुनियादी ढांचे का अभाव।
- दक्षिण एशिया की दयनीय स्थिति।
- घुसपैठ और आतंकवाद के आरोपों के कारण सीमापार और संघर्ष और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक अस्थिरता है परन्तु इन सभी समस्याओं एवं बाधाओं के बावजूद दक्षिण एशिया में सार्क के माध्यम से इसके सभी सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर को उपर उठाने में यह संगठन सहायक हो सकता है।

3.5. सार्क की सफलता के लिए प्रमुख सुझाव

सार्क देशों के मध्य किस प्रकार से आपसी समझ, विश्वास तथा राजनीतिक, आर्थिक सहयोग बढ़ाकर के इसको सफल बनाया जा सकता है। इसके लिए निम्न सुझाव दिये गये हैं:

- सर्वप्रथम सदस्य राष्ट्रों को महाशक्तियों के हस्तक्षेप को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
- सदस्य देशों को अन्त्तराष्ट्रीय मंचों पर विवादास्पद एवं संघर्षपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा पारस्परिक सहयोग एवं सर्व सम्मत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- सभी सदस्य राष्ट्रों को द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- सदस्य देशों को रक्षा बजट में कमी करनी चाहिए।
- सांस्कृतिक संपर्क एवं आवाजाही को प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाए।
- प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के उपायों को खोजना चाहिए।

4. भविष्य तथा पुनरूथान की आवश्यकता

जैसे-जैसे वैश्विक परिदृष्य बदल रहा है, सार्क के उद्देश्य भी विकसित होते जा रहे हैं। अतः बदलती हुई परिस्थितियों में सार्क देशों को निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है तभी इस संगठन की महत्ता एवं प्रासंगिकता बनी रह पाएगी।

- सदस्य देशों को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सहयोग करना चाहिए ताकि क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान किया जा सके।
- आपदा प्रबंधन के संदर्भ में कदम उठाया जा सकता है।
- राज्यों के मध्य पारस्परिक समझ और संचार तंत्र के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क करके, व्यापार के अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है।
- सार्क देशों में उप-क्षेत्रीय संगठन बनाने की पहल की गई है सदस्य राष्ट्रों को गणतंत्रीय एकता की उपेक्षा करने वाली इस प्रकार के पहलू से दूर रहना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि बिम्सटेक जैसे उप-क्षेत्रीय पहलों का निर्माण करके पाकिस्तान को अलग-थलग किया जाता है तो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा इसलिए हैं, क्योंकि अन्त्तराष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी दृष्टिकोण इस ओर संकेत करता है कि एक आर्थिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ एवं सशक्त पाकिस्तान, भारत के ही हित में है क्योंकि इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि द्विपक्षीय शक्ति संघर्ष जैसे तत्व सार्क के सक्रिय संचालन तथा प्रगति में अवरोधक रहे है।
- आसियन जैसे संगठन से दक्षेस को यह सीखने की आवश्यकता है कि दक्षेस को अपने सीमित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए क्योंकि सीमित लक्ष्यों को संगठन की कार्यक्षमता के अनुरूप प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्त्तराज्जीय व्यापार को बढ़ाने तथा पारस्परिक आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए सार्क को अपने नियमों को उद्दार बनाना होगा। इन्हीं प्रमुख बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए यह संगठन भविष्य में अपनी प्रासंगिकता एवं उपयोगिता को कायम रख सकता है।

5. निष्कर्ष

पस्तुत शोध पत्र के विवरण के अनुरूप कहा जा सकता है कि दक्षिण ऐशिया के देश सार्क के माध्यम से अपना आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी विकास तथा शान्तिपूर्ण सहयोग के प्रति संकल्पबद्ध है। क्योंकि अन्त्तराष्ट्रीय संबंधों में क्षेत्रीय शक्ति संरचना को आकार देने तथा इसकी दिशा

और दशा निर्धारित करने में क्षेत्रीय संगठन अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। परन्तु कुछ विद्वान बिम्सटेक को सार्क का विकल्प मानते हैं परन्तु क्षेत्रीय प्रगति एवं विकास के लिए सार्क की भूमिका सकारात्मक एवं कई महत्वपूर्ण संभावनाओं से परिपूर्ण है। परन्तु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह संगठन अपनी पूर्ण क्षमताओं, प्राकृतिक संसाधनों तथा वैविध्यपूर्ण अवसरों को उपयोग नहीं कर पाया है क्योंकि इन राष्ट्रों के मार्ग में अनेक बाधाएं रही हैं जैसे द्विपक्षीय तनाव, असंतुलित व्यापार, बुनियादी ढांचे की कमी तथा आतंकवाद। अतः उपरोक्त सभी संस्थागत तथा क्षेत्रीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर सहमत हुआ जा सकता है कि सार्क की भूमिका और इसके सक्रिय योगदान की पूर्ति कोई अन्य संगठन नहीं कर सकता है। सार्क में अभी भी एक कुशल और सकारात्मक परिणाम देने वाले क्षेत्रीय संगठन के रूप में उभरने की क्षमता है, जिससे साझा उद्देश्यों, कार्य योजनाओं, व्यापार वार्ताओं तथा सांस्कृतिक सहयोग की परियोजनाओं को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है।

संदर्भ

अनिल यादव, "सार्क के देशों में आपसी सुदृढ़ीकरण पड़ौसी संबंध", रिव्यम ऑफ़ रिसर्च, वा० 8, अंक 5, फरवरी 2019 और उपमा चतुर्वेदी, बी० भल्ला० और अमीन हसन "दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ", स्त्रोत इंनटरनेट.

आर० सी० गौड, एवं मनीषा मुखर्जी, भारत-श्रीलंका संबंधः सार्क का सुदृढ़ीकरण, एलाईड पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2013.

एम० एच० सैयद, सार्क राष्ट्रों का विश्वकोष, कल्पज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012.

इमामुअल नाहर, सार्कः समस्याएं एवं संभावनाएं, सहगल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1991.

गरिमा यादव और अनुराधा सिंह, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ हयूमनिटिज एण्ड शोसल साईंसिज, "दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के समक्ष चुनौतियां," वा० 10, न० 2, अप्रैल 2014.

जे० के० विश्वकर्मा, "प्राबलम्स एण्ड प्रोस्पेक्ट्स फॉर द साऊथ ऐशियन ऐसोसिएशन फॉर रिजनल कोआपरेशन (सार्क) पॉलिटिक्स एण्ड पॉलिसी, अक्टूबर, 2021.

पदमाजा मूर्ति, "सार्क और बिम्सटेकः क्षेत्रीय सहयोग में उनके अनुभव को समझना" ब्रीफिंग पेपर, क्यूट्स इनटरनेशन, 12, 2008.

मोहम्मद अमीनल करीम "साऊथ एशियन रिजनल इंटिग्रेशनः चेलेंजिज एण्ड प्रोस्पेक्ट्स," जेपनिज जर्नल ऑफ़ पॉलिटिक्ल साईंस, वा० 15, न० 02, जून 2014.

मनीष कुमार श्रीवास्तव, "दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठनः एक विश्लेषणात्मक अष्ययन" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसपलेनरी रिसर्च एण्ड डिवलपमैन्ट.

मोहम्मद मुस्तफा हुसैन और मोहम्मद इरशादुल करीम, "दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) पर एक शोध मार्गदर्शिका," ग्लोबलेक्स, सितम्बर-अक्टूबर, 2023.

संगीत विजय एवं दीपिका शर्मा, "21सवीं सदी में दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस): समस्याएँ एवं संम्भावनाएँ" इंटरनेशनल जर्नल आॅफ रिसर्च इन सोशल सांइंसिज, वा० 9, न० 3, मार्च 2019.

एस० एम० अजहारूल इसलाम, "रिवेटेलाइजिंग सब-रिजनल कोआपरेशन इन साऊथ एशिया" बी० आई० पी० एस० एल०, नवम्बर 2021.

सोनी यादव, "सार्क के माध्यम से भारत का पड़ौसी देशों के साथ संबंधः चुनौतियाँ एवं समाधान," जर्नल ऑफ़ अमरजिंग टेक्नोलॉजीज एण्ड इनोवेटिव रिसर्च" वा० 9, अंक 7, जुलाई 2022.

सुरेश ढांडा, "भारत और क्षेत्रीय संगठनः सार्क, आसियान और यूरोपियन संघ," (सम्पा०) भारत की विदेश नीति -स्त्रोत इंटरनेट तथा सी० पी० सिंह 2010.

डबल्यू० झाँग,"दक्षिण एशियाई आर्थिक सहयोग सुदृढीकरणः मौजूदा बाधाओं के बीच सक्षमकर्ता," 16 जनवरी 2015, इंटरनेट.